विचार बिन्दु

मस्तिष्क इन्द्रियों की अपेक्षा महान है, शुद्ध बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से महान है, आत्मा बुद्धि से महान है, और आत्मा से बढकर कुछ भी नहीं है। –स्वामी शिवानंद

हमारे बच्चे और सोशल मीडिया

क्या आप जानते हैं कि हम भारतीय सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करते हैं? शायद यह बात आपके लिए भी चौंकाने वाली हो कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम भारतीय ही करते हैं। हमारे यहां एक व्यक्ति औसतन 11 प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहता है और हर दिन लगभग 7.3 घण्टे स्क्रीन पर (मोबाइल या अन्य) व्यतीत करता है। समझा जा सकता है कि जब बड़े इतना समय स्क्रीन को देते हैं तो अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करने से शायद ही रोक पाते होंगे। वैसे भी कोरोना काल में तत्कालीन विवशताओं की वजह से शिक्षा के लिए मोबाइल का प्रयोग अपरिहार्य हो गया था। जो मां–बाप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते थे उन्हें भी आगे बढ़कर अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देना पड़ा था। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि उनमें से बहुत सारे लोग उस मोबाइल को वापस लेना भूल गए हों।

हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अधिकांश मां–बाप अपने बच्चों के प्रति अपने लाड़ का प्रदर्शन करने के लिए औचित्य की बहुत सारी सीमाओं की अनदेखी कर जाते हैं। वे बच्चों को बिना रोक–टोक के फास्ट फूड का उपभोग करने देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र बनें उससे पहले वे उन्हें अपने वाहनों की चाबियां सौंप देते हैं और लाड़–लाड़ में न केवल उन्हें मोबाइल का निर्बाध प्रयोग करने देते हैं, ख़ुद आगे बढ़कर उन्हें मोबाइल खरीद कर भी दे देते हैं। अगर मां–बाप न दें या देने की स्थिति में न हों तो बच्चे ख़ुद लड़–झगड़कर हासिल कर लेते हैं। बहुत बार यह भी देखा गया है कि ये सारी गतिविधियां करते हुए मां–बाप लज्जित नहीं गर्वित होते हैं।

इन बहुत सारी बातों के बीच से आज हम चर्चा यह करना चाह रहे हैं कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया का निर्बाध या सीमित उपयोग करने देना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा की है कि सन 2025 की पहली दिसम्बर से वहां सोलह बरस से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इस निषेध का उल्लंघन करने पर यूट्यूब को 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्थात लगभग 282 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। असल में वहां की सरकार ने एक अध्ययन करवाया था जिससे ज्ञात हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 12 बरस की आयु के 68 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि वह बच्चों को ख़तरनाक स्टंट, हिंसा, डरावने दृश्यों और अश्लीलता भरे वीडियो या शॉर्ट्स बार–बार दिखाता है। इस कारण इन बच्चों में बहुत तेज़ी से डोपामाइन साइकल बनने लगा है और इसका कुप्रभाव उनकी नींद, पढ़ाई और मानसिकता पर पड़ रहा है। यहीं यह भी जान लें कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फ़ेसबुक का प्रयोग पहले से वर्जित है।

इसी क्रम में यह भी जान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर बंदिशें लागू हैं। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बग़ैर माता–पिता की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे इतना ही पर्याप्त न हो वहां तो 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों द्वारा मोबाइल के उपभोग को पूरी तरह बंद करने के मामले में भी एक ट्रायल चल रही है। फ्रांस की ही तरह जर्मनी में भी 13 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे बग़ैर मां–बाप की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बेल्जियम में यह प्रतिबंध 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रभावी है।

> **हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा। अधिकांश मां-बाप में इस समझ का अभाव है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न उत्साह और न इच्छा।**

चीन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत कड़े नियम लागू हैं। वहां टिकटॉक के चीनी संस्करण के नियमित उपयोग की दैनिक सीमा केवल 45 मिनिट है और रात 10 से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग किया ही नहीं जा सकता है। युनाइटेड किंगडम का 2023 का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़े प्रतिबंध लागू करता है। इसमें उपयोग कर्ता की उम्र का सत्यापन भी शामिल है। दक्षिणी कोरिया में काफी पहले, सन 2011 में ही शटडाउन कानून लागू कर दिया गया था जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेमिंग का प्रयोग करने से रोका गया था। यह बात अलग है कि वहां बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। संयुक्त राज्य अमरीका में चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के अन्तर्गत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्रित करना वर्जित है। और यूरोपीय संघ, फ्रांस और स्पेन जैसे देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग के लिए मां–बाप की सहमति अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अब ज़रा एक नज़र अपने देश की स्थिति पर भी डाल लें। अप्रैल 2024 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद का विचारणीय विषय बताते हुए इस याचिका को खारिज़ कर दिया। असल में अभी भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपभोग को प्रतिबंधित करने पर कोई गंभीर विचार नहीं हो रहा है। इसकी बजाय हम सामाजिक सहमति, अभिभावकों के विवेक और डेटा सुरक्षा पर भरोसा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया और स्क्रीन के प्रयोग, प्रयोग के सीमा उल्लंघन और प्रयोग के ख़तरों से हम सभी वाक़िफ़ हैं। बच्चों के हाथ में जब स्क्रीन होता है तो वे उस पर किस तरह का कंटेंट देखते हैं, इस बात पर बड़ों का बहुत कम नियंत्रण संभव होता है। भारत जैसे देश में जहां मां–बाप अपनी रोज़ी–रोटी की समस्याओं में बहुत बुरी तरह उलझे होते हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि वे यह देखेंगे कि बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं, उनके प्रति ज़्यादती ही होगा। स्कूलों की जो हालत है,ख़ास तौर पर सरकारीस्कूलों की, वहां काम के बोझ से दबे (और कभी–कभी काम से बचने वाले भी) अध्यापकों से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यह भी सही है कि आज मोबाइल हम सबके लिए इतना अपरिहार्य हो गया है कि उससे बच्चों को वंचित रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है। मोबाइल तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और जब आप उन्हें यह उपकरण सौंप देंगे तो फिर वे उसका कैसा उपयोग करेंगे, यह तय करना आपके लिए बहुत कठिन है।

और बात केवल बच्चों ही नहीं है। यह भी देखा जाए कि बड़े भी मोबाइल के किस तरह एडिक्ट हो चुके हैं। इस बात की विस्तृत विवेचना अनावश्यक है। अब जो मां–बाप ख़ुद मोबाइल से चिपके हुए हैं वे अपने बच्चों को इसका प्रयोग करने से कैसे रोकेंगे? बहुत बार तो हम देखते हैं कि मां–बाप इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका शिशु मोबाइल के बग़ैर खाना तक नहीं खाता है या उनका बारह वर्ष का बेटा किस फर्राटे से स्कूटर दौड़ाता है। यह बताते हुए उनके चेहरे पर अपराध बोध नहीं गर्व झलकता है। बहुत सारे शिक्षक बताते हैं कि अगर वे बच्चों को फास्ट फूड का प्रयोग करने से रोकते हैं तो उनके मां बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं।

ऐसे में भारत जैसे देश की स्थितियां अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा। अधिकांश मां–बाप में इस समझ का अभाव है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न उत्साह और न इच्छा। ऐसे में जो समझदार लोग हैं वे दुखी होते रहेंगे, और उनके बच्चे यह देखकर अपने मां–बाप पर कुढ़ते रहेंगे कि उनके अन्य दोस्तों के मां–बाप जिस काम के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं, उसी काम के लिए उनके मां–बाप उनसे रोज़ किच–किच क्यों करते हैं! ऐसे में बस यही संभावना बची रहती है कि जो मां–बाप इस बात को समझते हैं वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया और स्क्रीन प्रयोग पर निगाह रखें और प्रयास करें कि बच्चे इनका सीमित प्रयोग करें।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

छात्रसंघों के चुनाव : छात्रों ने बजाया आंदोलन का बिगुल

बालमुकुंद ओझा

राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीते 2022 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए है। छात्रों के साथ ही छात्र संगठन लगातार चुनाव की मांग करते आ रहे हैं। गहलोत सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव स्थगित किये थे। इसके बाद आई भाजपा सरकार ने भी चुनाव कराने की कोई घोषना नहीं की है। दिल्ली विश्व विधालय छात्र संघ के चुनावों के बाद राजस्थान में भी छात्र संघों के चुनावों की मांग जोर शोर से उठ रही है। राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं छात्र संघों के चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। छात्रों ने सरकार द्वारा छात्र संघों के चुनाव नहीं कराने के फैसले के विरोध में उठा आंदोलन शुरू किया है। इसको लेकर छात्र संघों व छात्र नेताओं का गुस्सा लगातार उबाल मार रहा है। छात्र राजनीति पूरी तरह ठप पड़ी है।छात्र नेताओं का कहना है लोकतंत्र का पहला दरवाजा छात्र संघ होता है। छात्र संघ से युवा निष्पक्ष चुनाव, मतदान व प्रचार का ककहरा सीखते हैं। निर्वाचित छात्रसंघ न होने से छात्रों की समस्याएं अनसुनी रह जा रही हैं और प्रतिनिधित्व का अभाव गहरी निराशा पैदा कर रहा है। छात्र संगठनों व छात्र नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार जान–बूझ कर चुनाव की प्रक्रिया को टालता आ रहा है। राजस्थान विश्व विधालय छात्र संघ देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

यहां के छात्र नेता सिर्फ यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आगे चलकर देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। जो इस सीढ़ी को चढ़ गया वह राजनीति के ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। छात्र संघ के कई नेता बाद में राजनीति के दिग्गज चेहरे भी बने हैं। प्रदेश में कई साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश की सियासत में छात्र राजनीति से निकले नेताओं का बोल बाला है। छात्र संघ चुनाव में राजनीति का पहला ककहरा सीखा जाता है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक तक हर स्तर पर प्रभावशाली नेता दिए हैं। छात्र संघ की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, जो न केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान का मंच रहा है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी दिशा देने वाला स्तंभ साबित हुआ है। समय की माँग है कि छात्र संघ को फिर से जीवित किया जाए।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों के मधे नज़र राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे है। गहलोत ने ही अपने कार्यकाल में चुनावों पर रोक लगाई थी जो भाजपा सरकार के दौरान भी बदसतूर जारी है। राज्य की राजनीति में आज भी कई ऐसे नेता उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया है। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी युवा है। जो अपने मताधिकार का उपयोग कर देश तथा प्रदेश की सरकारें बनाती हैं। इतनी बड़ी आबादी का वोट सरकारें तय करती है। दूसरी तरफ छात्र संघों के चुनाव प्रदेशभर में प्रतिबंधित हैं। यह विचारणीय है।

एक छात्र नेता ने यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले राजस्थान के प्रसिद्द नेताओं के कटआउट लगाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाए कटआउट के जरिये बताया गया कि अनेक नेता और मंत्री छात्र संघों के जरिये सियासत में अपनी मज़बूत स्थिति संभाले हुए है। छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही आज देश और प्रदेश को ऐसे संघर्षशील नेता मिलें है जो हर परिस्थिति मैं पीड़ितों ओर शोषितों की आवाज मजबूती से उठाते है। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। प्रदर्शन में छात्र राजनीति से निकल मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बनने वाले अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, कालीचरण सर्राफ, हनुमान बेनीवाल, रघु शर्मा, सतीश पूनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, विकास चौधरी, महेंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, मनीष यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, रामलाल शर्मा,मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, अभिमन्यु पूनिया और राजकुमार शर्मा के कट–आउट लगाए थे।

सरकार ने लिंगदोह समिति की शर्तों की पालना नहीं होना भी चुनाव नहीं कराने का एक कारण बताया है। देखा जाता है छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह समिति की अचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। चुनाव एक मखौल बनकर रह जाता है। जाति और धनबल का खुला प्रदर्शन देखने को मिलता है। हिंसात्मक घटनाएं आम हो गई है। लिंगदोह समिति ने देश के विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों के लिए कुछ सिफारिशें जारी की थीं, जिनका उद्देश्य बाहुबल और धनबल के प्रभाव को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना था। सिफारिशों के अनुसार, कोई छात्र केवल एक बार चुनाव लड़ सकेगा, और चुनाव में अधिकतम 5,000 रुपये खर्च किए जा सकेंगे। उम्मीदवार और उनके संगठन पर चुनावी चंदा लेने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, विज्ञापन और बैनर पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा कॉलेज परिसर में किसी प्रकार के हथियार लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा, और उस साल की परीक्षा में भी वह वंचित हो जाएगा। वास्तविकता में लिंगदोह समिति की सिफारिशें कागजों में दबकर रह गई है।

–बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का सफर - राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

डॉ. अमृता कटारा

जयपुर। राजस्थान के राजकीय विद्यालय अब परंपरागत शिक्षण विधियों से आगे बढ़कर डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। ब्लैकबोर्ड और किताबों की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अब कक्षाएं स्मार्ट स्क्रीन, प्रोजेक्टर और डिजिटल कंटेंट से सजी हैं। राज्य सरकार की सूचना एवं संचार तकनीक योजना के तहत वर्ष 2024 तक 13,976 सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब्स की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से 13,411 लैब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत हैं जबकि 565 आदर्श विद्यालयों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। प्रदेश के 13 हजार से अधिक विद्यालयों में 17,421 स्मार्ट क्लासों की स्थापना भी की गयी है।

इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थी अब बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के साथ ई–मेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयर पर कार्य करना, इंटरनेट सर्चिंग, विषय आधारित वीडियो लेक्चर देखना और इंटरएक्टिव डिजिटल कंटेंट से परिचय भी सीख रहे हैं। इससे खासतौर पर ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थी तकनीकी साक्षरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर की शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षक- विद्यार्थी दोनों हो रहे डिजिटल रूप से दक्ष-ये प्रयोगशालाएं केवल उपकरणों का जमावड़ा भर नहीं हैं बल्कि यह एक सशक्त डिजिटल कक्षा के रूप में विकसित की गई हैं, जहां विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता के साथ–साथ आत्मविश्वास, संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता जैसे जीवनोपयोगी गुणों का भी विकास हो रहा है। प्रत्येक लैब में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, आवश्यक शैक्षिक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। साथ ही फर्नीचर, पावर बैकअप और सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखा गया है ताकि तकनीकी शिक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित आईसीटी प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति की गई है जो न केवल लैब का संचालन करते हैं बल्कि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षण में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। यह शिक्षक समय–समय पर विद्यालय के अन्य स्टाफ व प्रशासन को भी डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं जिससे विद्यालय समग्र रूप से डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

तकनीक बनी सीखने का माध्यम- आज के विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से विषयवस्तु की खोज करने, डिजिटल नोट्स तैयार करने, वर्चुअल क्विज़ में भाग लेने और ऑनलाइन कक्षाओं का हिस्सा बनने में पूरी तरह सक्षम हो रहे हैं। आईसीटी लैब्स एवं स्मार्ट क्लास ने विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। अब विद्यार्थी कंप्यूटर को केवल गेमिंग या मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अपने भविष्य निर्माण का एक शक्तिशाली औजार समझने लगे हैं। राज्य के शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर ई–क्लास वीडियो, एनिमेटेड प्रजेंटेशन और पावरपॉइंट लेक्चर जैसे डिजिटल कंटेंट समय–समय पर तैयार किए जा रहे हैं। ये सामग्री आईसीटी लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। इससे न केवल विद्यार्थियों की समझ में सुधार हुआ है बल्कि विज़ुअल लर्निंग के कारण उनकी याददाश्त और विषय पर पकड़ भी पहले से बेहतर हो रही है। यह दृष्टिकोण परंपरागत शिक्षा प्रणाली से हटकर एक सहभागी और बहुआयामी शिक्षण वातावरण की ओर बढ़ता कदम है।

मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा राजस्थान -शिक्षा विभाग के प्रयास और सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से राज्य के राजकीय विद्यालय अब डिजिटल इंडिया की रफ्तार से कदमताल कर रहे हैं। आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लास न केवल विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही हैं। यह पहल राजस्थान को न केवल डिजिटल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

–डॉ. अमृता कटारा,
सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

मीरा महोत्सव में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये

मेड़ता सिटी, (निसं)। विश्व ऐतिहासिक चारभुजानाथ के 521वें मीरा जयंती महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिरकत की।

महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया व महोत्सव में मीरा स्मारक के कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू, खींवसर विधायक रेवतराम डांगा, जनता प्रधान संदीप चौधरी, मेड़ता नगरपालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी, किन्नर समाज गादीपति राजकुमारी बाई कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष व पूरी टीम के द्वारा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये।

इस मौके पर दीया कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेड़ता मीरा की नगरी है, यहां आने का मौका इस महोत्सव में ही मिलता है। दीया कुमारी ने कहा कि मेड़ता में जो भी विकास कार्य होंगे वो गुणवत्ता के साथ होंगे। मेड़ता में एक पैरोनमा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। भारत सरकार व राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वहीं जहां पर कोई भगवान या भक्त सहित कई लोगों के सर्किल उनके नाम से निर्माण कराने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा आयेगा उस पर कार्य किए जाएंगे।

महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने कहा मेड़ता भक्ति भाव की नगरी है। यहां के नागरिक प्रेम भाव से भरे हुये हैं। मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा मीरा महोत्सव को सरकारी कैलेंडर में स्थान दिलाने पर पूरा मेड़ता इनका आभारी है। मेड़ता से इनका सम्बन्ध पुराना है। इसलिए मेड़ता क्षेत्र में विकास की गंगा बही है और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, जितेंद्र गहलोत मीरा महोत्सव समिति अध्यक्ष, सचिव रविप्रकाश कमेडिया, विरमदेव सिंह जैसास, अभय सिंह भेसड़ा, ऋषभ राठी, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, उमा शर्मा रजत, दशरथ सारस्वत, कैलाश गौड, मोहित माली, रवि गहलोत सहित कई लोग मौजूद थे।

मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महिलाओं के साथ भजनों का आनंद लिया।

- ‘मेड़ता में एक पैरोनमा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है’
- दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 4 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:13 तक, ब्रह्म योग प्रातः 7:05 तक, गर करण दिन 11:42 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–कर्क, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–कन्या, बुध–कर्क, गुरू–मिथुन, शुक्र–मिथुन, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से प्रातः 9:13 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन–रात रहेगा। भद्रा रात्रि 12:47 से आरम्भ होगी। आज चतुर्थ सावन वन सोमवार व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः अमृत सूर्योदय से 7:36 तक, शुभ 9:15 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ–अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09

मेष
पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी अनबन–मतभेद हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी।